

बोकारो जिला में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन : चुनौतियां एवं समाधान

राजेश महतो

शोधछात्र

शिक्षाशास्त्र विभाग

राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड)

शोध-सार

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इस शोध में झारखंड राज्य के बोकारो जिले में इस योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि योजना को लागू करते समय कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तथा उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। शोध के दौरान यह पाया गया कि बोकारो जिले में SSA के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ सामने आती हैं। इनमें प्रमुख हैं—शिक्षकों की कमी, अधोसंरचना का अभाव (जैसे कि शौचालय, पेयजल, बिजली), बालिका शिक्षा में रुचि की कमी, अनुसूचित जाति व जनजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, तथा स्कूलों में उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री की अनुपलब्धता। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर निगरानी की कमी और धन के समय पर उपयोग न हो पाना भी प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं। समाधान स्वरूप, शोध में सुझाव दिया गया है कि SSA को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों की नियमित नियुक्ति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, शिक्षा पर विशेष जागरूकता अभियान, बालिकाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ तथा ICT आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही, प्रशासनिक निगरानी को भी सशक्त किया जाना आवश्यक है।

कुंजी शब्द : सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण

परिचय

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2000-01 में शुरू किया गया था, ताकि 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता सुधार, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना है। यह शोध एसएसए के क्रियान्वयन की स्थिति, प्रभावशीलता, और विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और शिक्षा पदाधिकारी) की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है। विभिन्न तालिकाओं में प्रस्तुत आंकड़ों के माध्यम से अलग-अलग पक्षों जैसे- विद्यालयों की संबद्धता, प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वित्तीय सहायता, शिक्षक नियुक्ति, बुनियादी ढांचा, बालिका शिक्षा, और छात्र उपस्थिति का मूल्यांकन किया गया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश हितधारक एसएसए के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, विशेष रूप से शिक्षक और शिक्षा पदाधिकारी, जो इसकी नीतियों और कार्यान्वयन से पूर्णतः अवगत हैं। हालांकि, अभिभावकों और समिति सदस्यों में जागरूकता और भागीदारी की कमी कुछ क्षेत्रों में देखी गई, जो सूचना प्रसार और सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

बोकारो जिले में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के क्रियान्वयन की स्थिति को समझने के लिए, 20 चयनित प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित हितधारकों—अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों, और सक्षम पदाधिकारियों (जैसे प्राचार्य, प्रधानाध्यापक) से प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं। इस अध्ययन के लिए, एसएसए से जुड़े विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले 10 प्रश्न तैयार किए गए, जिनके आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्रत्येक पहलू, जैसे विद्यालय की संबद्धता, प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वित्तीय सहायता, शिक्षक नियुक्ति, बुनियादी ढांचा, बालिका शिक्षा, और छात्र उपस्थिति, को अलग-अलग विश्लेषित किया गया। इस विश्लेषण में अवलोकन और विशेष साक्षात्कारों से प्राप्त जानकारी को भी आंकड़ों के साथ

जोड़ा गया, ताकि एक समग्र और गहन समझ विकसित की जा सके। यह दृष्टिकोण न केवल हितधारकों की धारणाओं को उजागर करता है, बल्कि व्यावहारिक चुनौतियों और सुधार के क्षेत्रों को भी रेखांकित करता है, जिससे एसएसए के प्रभावी कार्यान्वयन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

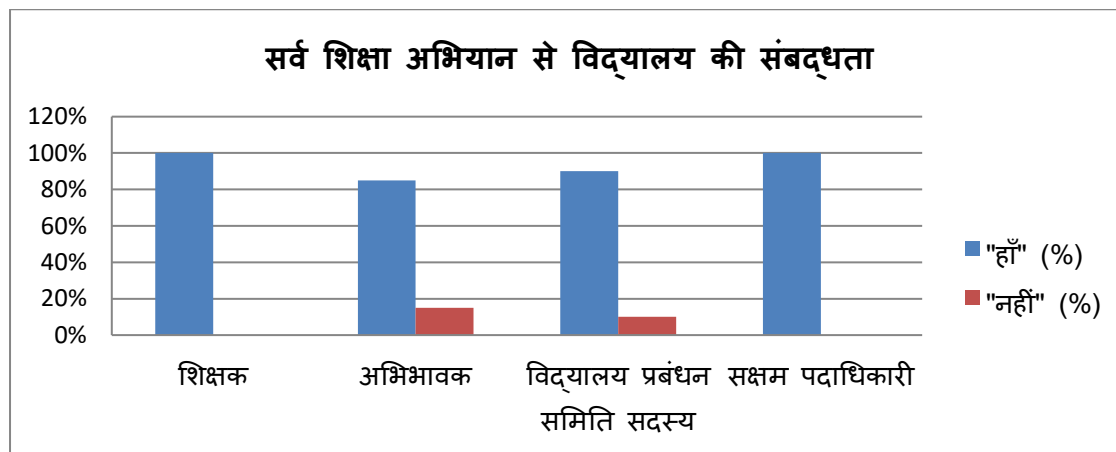
○ बोकारो जिला में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन

सर्व शिक्षा अभियान से विद्यालय की संबद्धता:

तालिका 1.1 वर्तमान अध्ययन के लिए चयनित विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) से संबद्धता के संदर्भ में हितधारकों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सक्षम पदाधिकारी (प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य) और शिक्षकों ने 100% सहमति जताई कि उनके विद्यालयों में एसएसए प्रभावी रूप से लागू है। यह उनकी योजना के प्रति पूर्ण जागरूकता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। शिक्षक और पदाधिकारी इस कार्यक्रम के तहत शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं, 85% अभिभावकों और 90% विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों ने संबद्धता की पुष्टि की, किंतु 15% अभिभावकों और 10% समिति सदस्यों ने असंबद्धता दर्शाई। यह असंबद्धता योजना के लागू न होने के बजाय उनकी जानकारी के अभाव को इंगित करती है। यह स्थिति सामुदायिक जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अतः, आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर सभी चयनित विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान प्रभावी है, लेकिन अभिभावकों और प्रबंध समिति सदस्यों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। इससे एसएसए का उद्देश्य सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में और सशक्त होगा।

तालिका 1.1: सर्व शिक्षा अभियान से विद्यालय की संबद्धता

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	20	100	00	0
2	अभिभावक	17	85	3	15
3	विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य	19	90	1	10
4	सक्षम पदाधिकारी	20	100	00	0



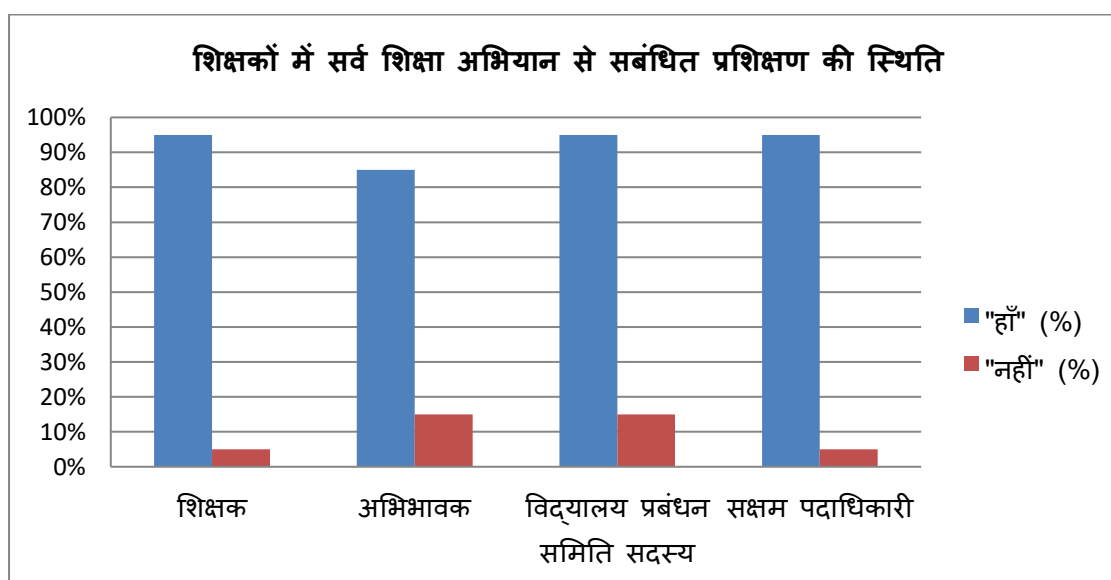
चित्र संख्या -1.1.

शिक्षकों में सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित प्रशिक्षण की स्थिति

तालिका 1.2 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) से संबंधित प्रशिक्षण की स्थिति को विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और सक्षम पदाधिकारी) के संदर्भ में दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित व्याख्या की जा सकती है। शिक्षकों में 95% (19) ने एसएसए से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने की पुष्टि की, जबकि 5% (1) ने नहीं, जो दर्शाता है कि लगभग सभी शिक्षक इस योजना के तहत प्रशिक्षित हैं, जो उनकी शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाता है। अभिभावकों में 85% (17) ने प्रशिक्षण/जागरूकता सत्रों में भागीदारी दिखाई, किंतु 15% (3) की असहमति सूचना या अवसरों की कमी को इंगित करती है। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों में भी 95% (17) ने प्रशिक्षण की पुष्टि की, जबकि 15% (3) ने नहीं, जो उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता की कमी को दर्शाता है। सक्षम पदाधिकारियों में 95% (19) ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने में सहायक है। कुल मिलाकर, आंकड़े बताते हैं कि एसएसए प्रशिक्षण अधिकांश हितधारकों तक पहुंचा है, लेकिन अभिभावकों और कुछ समिति सदस्यों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और प्रयास आवश्यक हैं। इससे योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और सशक्त होगा।

तालिका 1.2: शिक्षकों में सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित प्रशिक्षण की स्थिति

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	19	95	1	5
2	अभिभावक	17	85	3	15
3	विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य	17	95	3	15
4	सक्षम पदाधिकारी	19	95	1	5



चित्र संख्या -1.2.

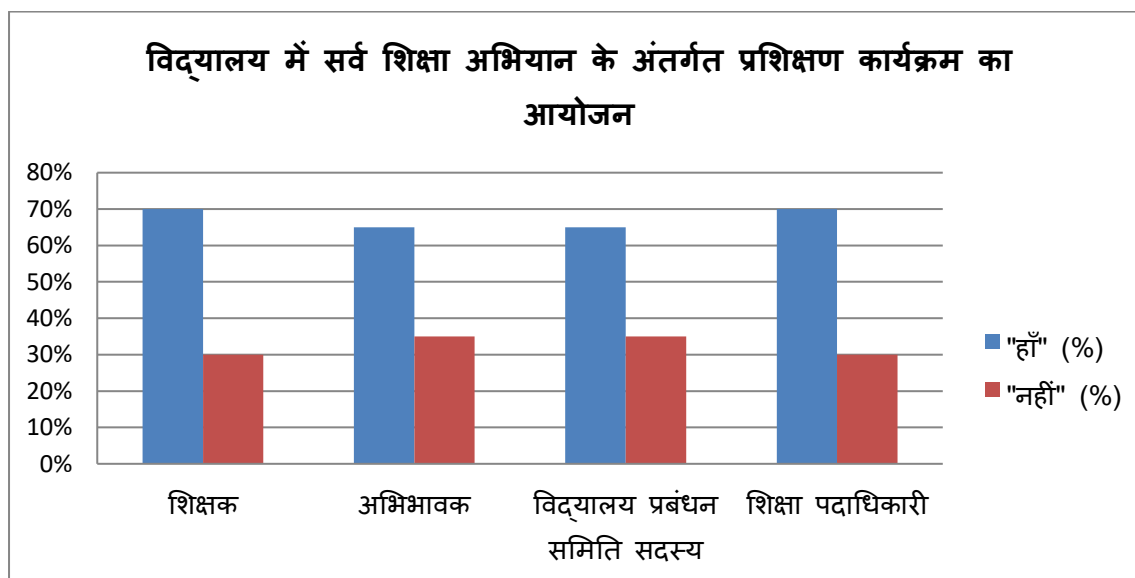
विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

तालिका 1.3 विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की स्थिति को विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और शिक्षा पदाधिकारी) के संदर्भ में दर्शाती है।

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षकों और शिक्षा पदाधिकारियों में 70% (14) ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की पुष्टि की, जबकि 30% (6) ने असहमति जताई। अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों में 65% (13) ने आयोजन की बात स्वीकारी, किंतु 35% (7) ने नहीं। यह नकारात्मक प्रतिशत (30-35%) इस बात को रेखांकित करता है कि प्रशिक्षण प्राप्त तो हुआ है, लेकिन यह निरंतर और नियमित नहीं है। यह अनियमितता एसएसए के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि निरंतर प्रशिक्षण शिक्षकों की गुणवत्ता, अभिभावकों की जागरूकता, और समिति सदस्यों की सक्रियता को बढ़ाता है। अतः, इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सभी हितधारकों तक नियमित और सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और प्रयास आवश्यक हैं। इससे सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त होगा।

तालिका 1.3: विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	14	70	6	30
2	अभिभावक	13	65	7	35
3	विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य	13	65	7	35
4	शिक्षा पदाधिकारी	14	70	6	30



चित्र संख्या -1.3

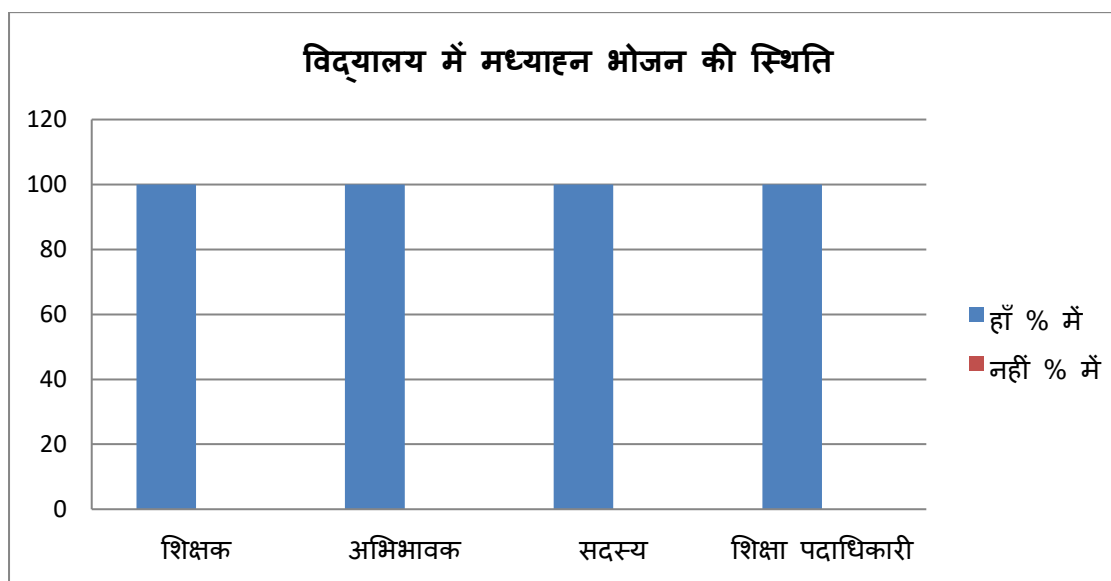
विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति

तालिका 1.4 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम की स्थिति को विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और शिक्षा पदाधिकारी) के दृष्टिकोण से दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार, सभी हितधारकों (20-20) ने 100% सहमति जताई कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम विद्यालयों में लागू है। यह शत-प्रतिशत सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि एमडीएम योजना विद्यालयों में सख्ती से लागू है, जो बच्चों की उपस्थिति और पोषण स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि, साक्षात्कार और अवलोकन से प्राप्त जानकारी के अनुसार,

भोजन की गुणवत्ता और संसाधनों की कमी प्रमुख चिंताएं हैं। कई विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है, और उचित प्रबंधन जैसे समय पर सामग्री की आपूर्ति और स्वच्छता में कमी देखी गई है। इन समस्याओं के बावजूद, सरकार विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इन कमियों को दूर करने के लिए कार्य कर रही है। अतः, तालिका यह दर्शाती है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

तालिका : 1.4. विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	20	100	0	0
2	अभिभावक	20	100	0	0
3	सदस्य	20	100	0	0
4	शिक्षा पदाधिकारी	20	100	0	0



चित्र संख्या - 1.4

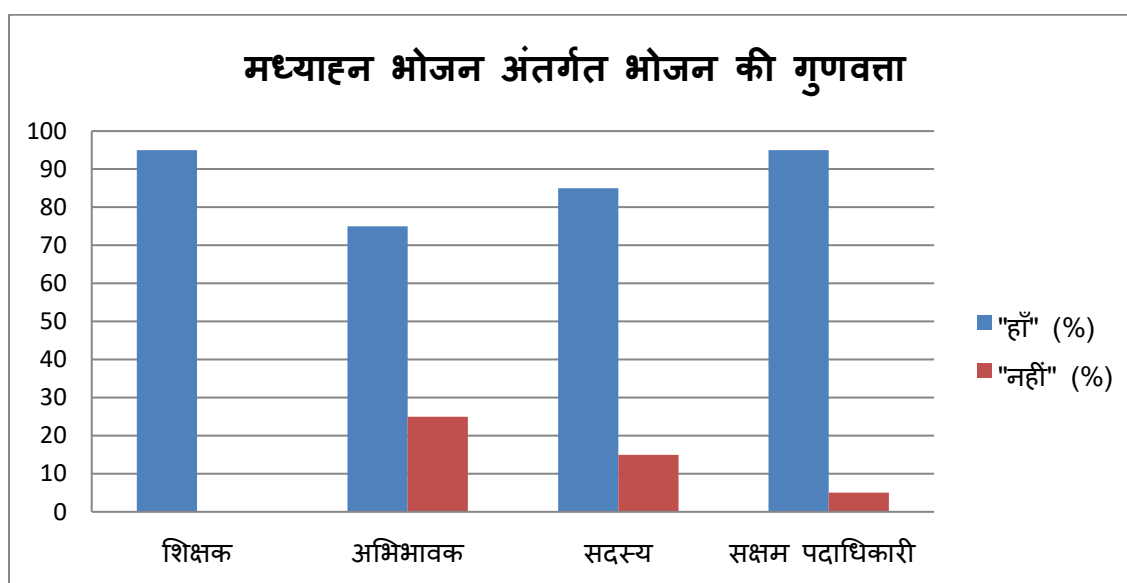
मध्याह्न भोजन अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता

तालिका 1.5 मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता के प्रति विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और सक्षम पदाधिकारी) की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार, शिक्षकों और सक्षम पदाधिकारियों में 95% (19) ने भोजन की गुणवत्ता को संतोषजनक माना, जबकि 5% (1) ने असहमति जताई। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों में 85% (17) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किंतु 15% (3) ने नहीं। अभिभावकों में 75% (15) ने गुणवत्ता की पुष्टि की, जबकि 25% (5) ने असंतोष व्यक्त किया। यह दर्शाता है कि भोजन की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षक और पदाधिकारी, जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन अवलोकन के दौरान भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, और संसाधनों की कमी जैसी खामियां सामने आईं। अभिभावकों की 25%

नकारात्मक प्रतिक्रिया संभवतः बच्चों द्वारा साझा की गई जानकारी से प्रभावित है, जो वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। अतः, एमडीएम की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार और विद्यालयों को स्वच्छता, सामग्री आपूर्ति, और प्रबंधन पर ध्यान देना होगा।

तालिका : 1.5. मध्याह्न भोजन अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	19	95	01	0
2	अभिभावक	15	75	5	25
3	सदस्य	17	85	03	15
4	सक्षम पदाधिकारी	19	95	01	05



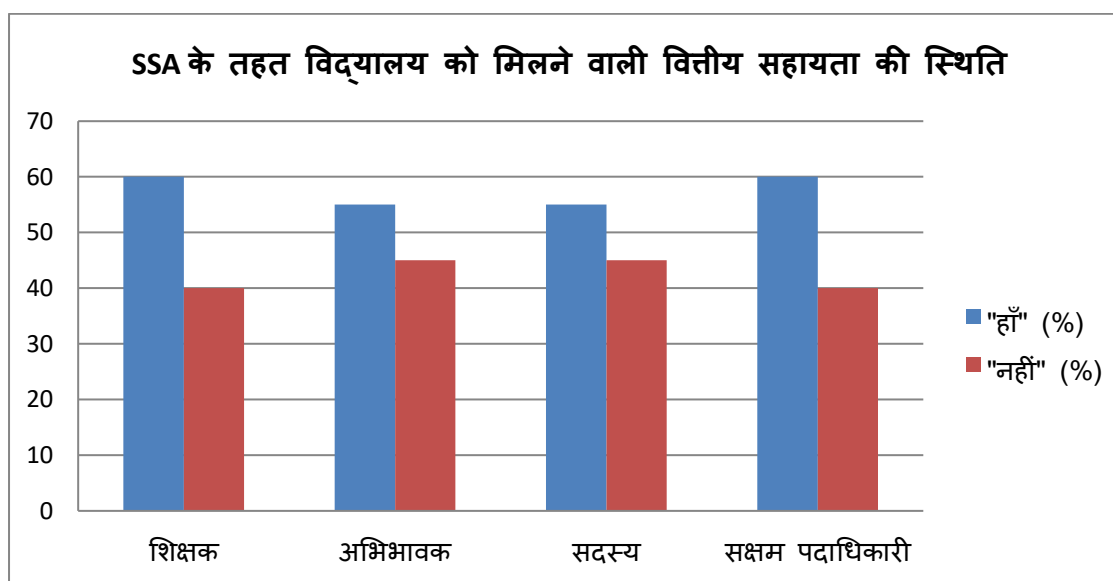
चित्र संख्या -1.5

SSA के तहत विद्यालय को मिलने वाली वित्तीय सहायता की स्थिति

तालिका 1.6 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत विद्यालयों को प्राप्त वित्तीय सहायता की स्थिति को विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और सक्षम पदाधिकारी) के दृष्टिकोण से दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार, शिक्षकों और सक्षम पदाधिकारियों में 60% (12) ने वित्तीय सहायता प्राप्त होने की पुष्टि की, जबकि 40% (8) ने असहमति जताई। अभिभावकों और समिति सदस्यों में 55% (11) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किंतु 45% (9) ने नहीं। यह अपेक्षाकृत उच्च नकारात्मक प्रतिक्रिया गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि एसएसए का सफल कार्यान्वयन निर्बाध और समयबद्ध वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए एसएसए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, किंतु वित्तीय सहायता की अनियमितता और देरी कई चुनौतियां पैदा करती है। अधिकांश प्राथमिक विद्यालय पैरा-शिक्षकों पर निर्भर हैं, जो कम वेतन पर काम करते हैं, और विकासात्मक गतिविधियों जैसे बुनियादी ढांचे, शिक्षण सामग्री, और प्रशिक्षण के लिए भुगतान में देरी होती है। अतः, वित्तीय सहायता की समयबद्ध उपलब्धता और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि एसएसए के उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरे हो सकें।

तालिका : 1.6. SSA के तहत विद्यालय को मिलने वाली वित्तीय सहायता की स्थिति

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	12	60	8	40
2	अभिभावक	11	55	9	45
3	सदस्य	11	55	9	45
4	सक्षम पदाधिकारी	12	60	8	40



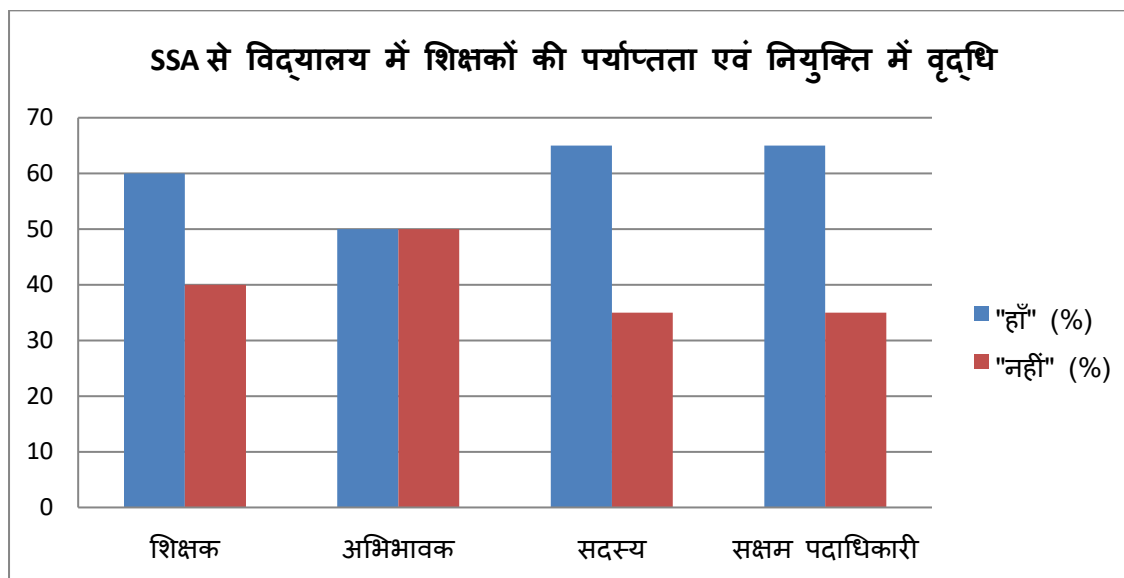
चित्र संख्या -1.6

शिक्षकों की पर्याप्तता एवं नियुक्ति:

तालिका 1.7 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्तता और नियुक्ति में वृद्धि के संबंध में विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और शिक्षा पदाधिकारी) की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार, शिक्षकों में 60% (12) और शिक्षा पदाधिकारियों में 65% (13) ने शिक्षकों की पर्याप्तता और नियुक्ति में वृद्धि की पुष्टि की, जबकि 40% (8) और 35% (7) ने असहमति जताई। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों में 65% (13) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किंतु 35% (7) ने नहीं। अभिभावकों में 50% (10) ने सहमति और 50% (10) ने असहमति दिखाई, जो शिक्षक-छात्र अनुपात और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता पर चिंता को रेखांकित करता है। यह अपेक्षाकृत उच्च नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और नियुक्तियों में देरी एक गंभीर समस्या है। एसएसए का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सशक्त करना है, लेकिन शिक्षकों की अपर्याप्तता इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है। अतः, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, नियमित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने, और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

तालिका : 1.7. SSA से विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्तता एवं नियुक्ति में वृद्धि

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	12	60	8	40
2	अभिभावक	10	50	10	50
3	सदस्य	13	65	7	35
4	सक्षम पदाधिकारी	13	65	7	35



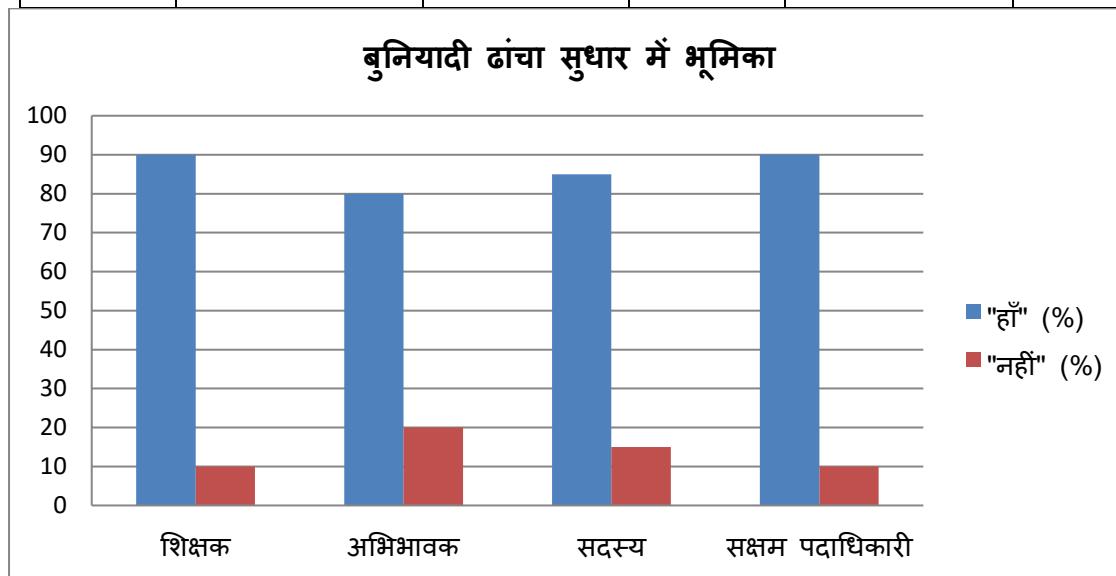
चित्र संख्या -1.7

बुनियादी ढांचा सुधार में भूमिका

तालिका 1.8 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत विद्यालयों में बुनियादी ढांचा सुधार के संबंध में विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और सक्षम पदाधिकारी) की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षकों और सक्षम पदाधिकारियों में 90% (18) ने पुष्टि की कि एसएसए के तहत बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, जबकि 10% (2) ने असहमति जताई। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों में 85% (17) और अभिभावकों में 80% (16) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किंतु क्रमशः 15% (3) और 20% (4) ने सुधार न होने की बात कही। यह उच्च सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि अधिकांश हितधारक कक्षाओं, शौचालयों, और शिक्षण सामग्री जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार को स्वीकार करते हैं। हालांकि, अभिभावकों और समिति सदस्यों की नकारात्मक प्रतिक्रिया जागरूकता की कमी या कुछ विद्यालयों में सुधार की अपर्याप्तता को दर्शाती है। बुनियादी ढांचा सुधार एसएसए का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो शिक्षण वातावरण को बेहतर बनाता है। अतः, सभी हितधारकों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

तालिका : 1.8. बुनियादी ढांचा सुधार में भूमिका

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	18	90	2	10
2	अभिभावक	16	80	4	20
3	सदस्य	17	85	3	15
4	सक्षम पदाधिकारी	18	90	2	10



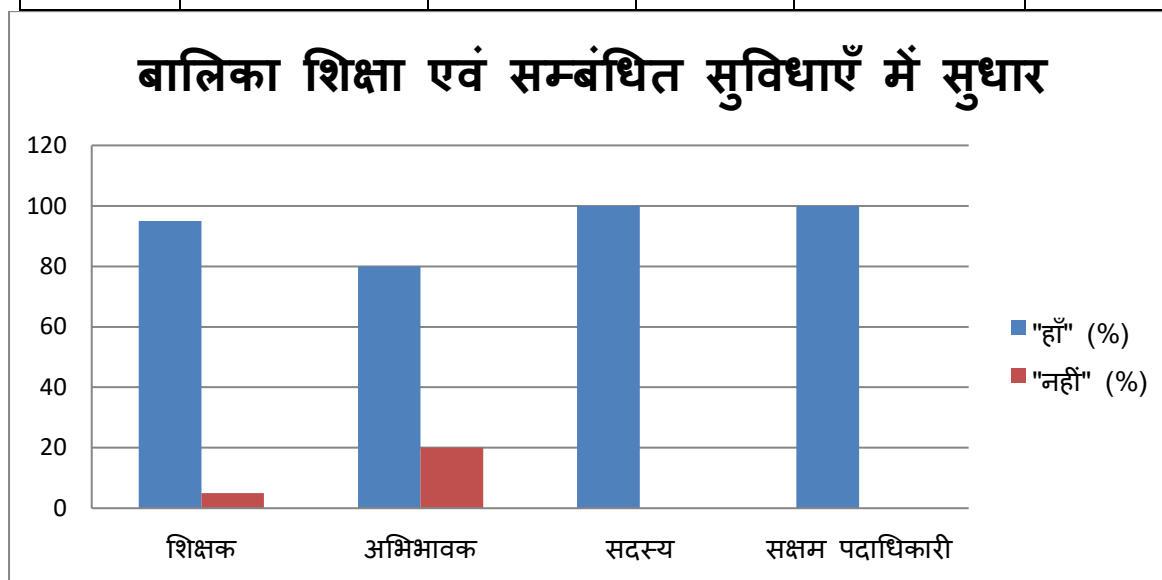
चित्र संख्या -1.8

बालिका शिक्षा एवं सम्बंधित सुविधाएँ में सुधार

तालिका 1.9 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत बालिका शिक्षा और संबंधित सुविधाओं में सुधार के संबंध में विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और सक्षम पदाधिकारी) की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों और सक्षम पदाधिकारियों में 100% (20) ने बालिका शिक्षा और सुविधाओं में सुधार की पुष्टि की, जो अत्यंत सकारात्मक है। शिक्षकों में 95% (19) ने सहमति जताई, जबकि 5% (1) ने असहमति दिखाई। अभिभावकों में 80% (16) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किंतु 20% (4) ने सुधार न होने की बात कही। यह उच्च सकारात्मक प्रतिक्रिया बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, जैसे अलग शौचालय, छात्रवृत्ति, और जागरूकता कार्यक्रमों में प्रगति को दर्शाती है। विशेष रूप से समिति सदस्यों और पदाधिकारियों की शत-प्रतिशत सहमति यह संकेत देती है कि नीतिगत स्तर पर प्रयास प्रभावी हैं। हालांकि, अभिभावकों की 20% नकारात्मक प्रतिक्रिया कुछ क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी या जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाती है। यह एक अच्छा संकेत है, किन्तु बालिका शिक्षा को और सशक्त करने के लिए अभिभावकों की जागरूकता और सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देना होगा।

तालिका : 1.9. बालिका शिक्षा एवं सम्बंधित सुविधाएँ में सुधार

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	19	95	1	5
2	अभिभावक	16	80	4	20
3	सदस्य	20	100	0	0
4	सक्षम पदाधिकारी	20	100	0	0



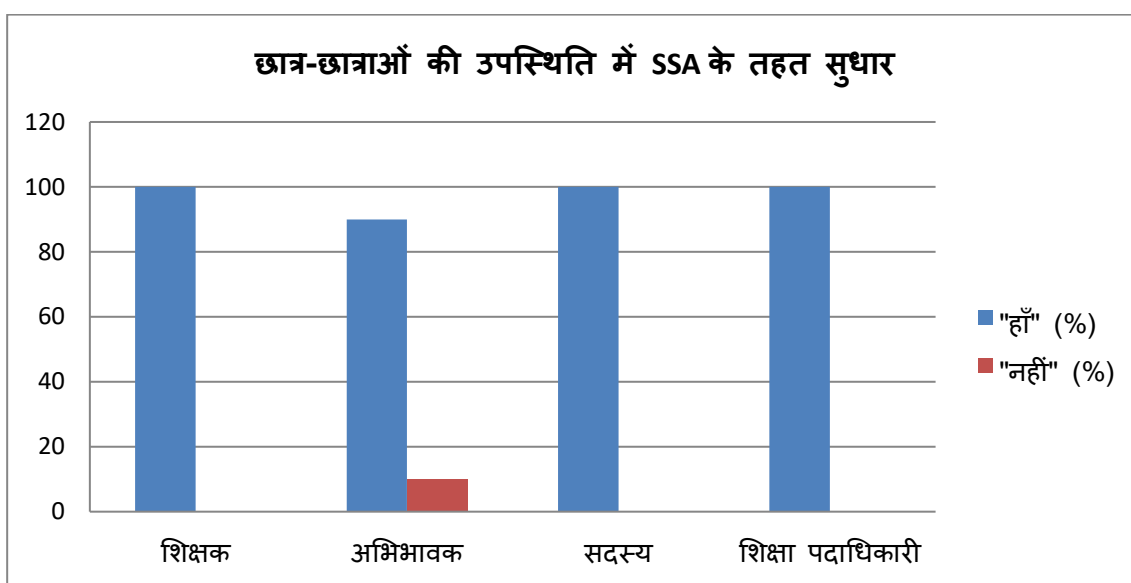
चित्र संख्या - 1.9

प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में सुधार

तालिका 1.10 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में सुधार के संबंध में विभिन्न हितधारकों (शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, और शिक्षा पदाधिकारी) की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों, और शिक्षा पदाधिकारियों में 100% (20) ने उपस्थिति में सुधार की पुष्टि की, जो अत्यंत सकारात्मक संकेत है। अभिभावकों में 90% (18) ने सहमति जताई, जबकि 10% (2) ने असहमति दिखाई। यह शत-प्रतिशत और उच्च सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि मध्याह्न भोजन, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, और बुनियादी ढांचा सुधार जैसे एसएसए के प्रयासों ने उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभिभावकों की 10% नकारात्मक प्रतिक्रिया संभवतः कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, सामाजिक-आर्थिक बाधाओं, या सुविधाओं की अपर्याप्तता को दर्शाती है। यह स्थिति शिक्षा की पहुंच और निरंतरता को और सशक्त करने के लिए सामुदायिक जागरूकता और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। कुल मिलाकर, तालिका यह स्पष्ट करती है कि एसएसए ने छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन अभिभावकों की शेष चिंताओं को दूर करने के लिए लक्षित प्रयास आवश्यक हैं।

तालिका : 1.10. छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में SSA के तहत सुधार

क्रम संख्या	हितधारक	"हाँ" (संख्या)	"हाँ" (%)	"नहीं" (संख्या)	"नहीं" (%)
1	शिक्षक	20	100	0	0
2	अभिभावक	18	90	2	10
3	सदस्य	20	100	0	0
4	शिक्षा पदाधिकारी	20	100	0	0



चित्र संख्या -1.10

- **बोकारो जिले में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) की प्रमुख चुनौतियाँ**
- **वित्तीय सहायता में असंगति:** SSA के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता समय पर नहीं पहुँचती या जरूरतों के अनुरूप नहीं होती। विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु धन वितरण में देरी या जटिल प्रक्रियाएँ योजना की प्रभावशीलता को बाधित करती हैं। इससे अनेक विकासात्मक कार्य अधूरे रह जाते हैं। तालिका 4.11 के अनुसार केवल 57.5% हितधारकों ने वित्तीय सहायता को संतोषजनक माना, जो साफ संकेत है कि इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।
- **शिक्षकों की कमी और नियुक्ति की समस्याएँ:** SSA के तहत शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी है, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहती है। तालिका के अनुसार मात्र 60% हितधारकों ने शिक्षकों की पर्याप्तता को स्वीकारा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, विद्यार्थियों की रुचि घटती है और कक्षा संचालन बाधित होता है। कई बार एक शिक्षक को एक साथ कई कक्षाएँ लेनी पड़ती हैं, जिससे छात्रों को पर्याप्त ध्यान नहीं मिल पाता। शिक्षक पदों की शीघ्र और पारदर्शी नियुक्ति एक बड़ी आवश्यकता है।
- **अभिभावकों की सीमित सहभागिता:** SSA की सफलता में समुदाय विशेषकर अभिभावकों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, परन्तु बोकारो में केवल 76.5% अभिभावकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उनकी अपेक्षाओं, जैसे भोजन की गुणवत्ता, भवन की स्थिति या बच्चों की पढ़ाई को लेकर असंतोष देखा गया। कई बार वे योजना के उद्देश्यों से अवगत नहीं होते, जिससे संवाद की कमी रहती है। जागरूकता अभियान, पीटीएम और सामाजिक सहभागिता कार्यक्रमों द्वारा

उन्हें योजना की प्रक्रिया में जोड़ना अनिवार्य है।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता:** शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, लेकिन बोकारो में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सीमित रही है। केवल 67% हितधारकों ने इन्हें सकारात्मक माना। कई बार प्रशिक्षण सैद्धांतिक होता है और स्थानीय समस्याओं को संबोधित नहीं करता। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आवृत्ति और विषयवस्तु में सुधार कर उसे व्यावहारिक और उपयोगी बनाना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को नई तकनीकों और समावेशी शिक्षा की विधियों से भी परिचित कराया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** हालाँकि तालिका में 86.2% हितधारकों ने ढांचे में सुधार को माना है, परंतु कुछ विद्यालयों में अब भी शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली और बैठने की व्यवस्था अपर्याप्त है। यह बच्चों की उपस्थिति और विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है। SSA के तहत स्वीकृत धन का समुचित उपयोग और नियमित निगरानी आवश्यक है ताकि भवन, कक्षा, पुस्तकालय और खेल सामग्री जैसे बुनियादी संसाधनों में सुधार हो सके।
- **बालिका शिक्षा को लेकर सामाजिक सोच:** बालिकाओं की शिक्षा को लेकर कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी रूढ़िवादी सोच है। भले ही 93.7% ने बालिका शिक्षा में सुधार को स्वीकारा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी भी जागरूकता की कमी है। किशोरावस्था, सुरक्षा, और मासिक धर्म जैसे मुद्दों पर उचित सुविधाओं और जानकारी के अभाव में कई बालिकाएँ पढ़ाई छोड़ देती हैं। इनके समाधान हेतु विशेष जागरूकता अभियान, अलग शौचालय, छात्रवृत्ति एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
- **निगरानी व मूल्यांकन की कमजोरी:** SSA योजनाओं की निगरानी व मूल्यांकन की व्यवस्था कमजोर है। शिक्षा अधिकारियों की सीमित संख्या और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण कई बार योजना की प्रगति का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। इससे कमजोर क्षेत्रों की पहचान और सुधार की प्रक्रिया बाधित होती है। सतत निगरानी प्रणाली, स्थानीय निकायों की सक्रियता और डिजिटल टूल्स के उपयोग से योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।

समाधान हेतु सुझाव :

1. SSA के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए।
2. रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, विशेषकर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों में, तथा दूर-दराज़ के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई जाएँ।
3. प्रशिक्षण को व्यावहारिक, क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर आधारित और ICT समर्थ बनाना चाहिए, जिससे शिक्षकों का कौशल बढ़े।
4. विद्यालय प्रबंधन समितियों में उनकी सक्रिय भागीदारी, जागरूकता अभियान और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों की अपेक्षाओं को समझा और संबोधित किया जा सकता है।
5. मध्याह्न भोजन, शौचालय, पेयजल और कक्षा कक्ष जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की नियमित निगरानी और सुधार से छात्रों की उपस्थिति एवं गुणवत्ता में वृद्धि संभव है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान (SSA) का अध्ययन क्षेत्र में क्रियान्वयन काफी हद तक प्रभावी रहा है, जिसने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कार्यक्रम विद्यालयों की संरचना को मजबूत करने, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है। मध्याह्न भोजन योजना ने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे न केवल

उपस्थिति में सुधार हुआ बल्कि पोषण संबंधी जरूरतों को भी संबोधित किया गया। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षकों के प्रशिक्षण ने शैक्षिक वातावरण को और सुदृढ़ किया है। हितधारकों, विशेष रूप से सक्षम शिक्षा पदाधिकारियों और शिक्षकों ने SSA के प्रयासों की सराहना की है, जो इसकी कार्यान्वयन क्षमता को दर्शाता है।

हालांकि, कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है। वित्तीय सहायता की उपलब्धता और शिक्षकों की पर्याप्तता व नियुक्ति जैसे पहलुओं में अपेक्षाकृत कम सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो संसाधनों के प्रभावी वितरण और नियोजन में कमी की ओर इशारा करता है। अभिभावकों की तुलनात्मक रूप से कम संतुष्टि से पता चलता है कि उनकी अपेक्षाओं, जैसे भोजन की गुणवत्ता या स्कूल सुविधाओं, को पूरी तरह से संबोधित करने की जरूरत है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी एक ऐसा क्षेत्र है, जहां और प्रयास किए जा सकते हैं ताकि शिक्षकों की क्षमता को और बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर, SSA ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, लेकिन वित्तीय प्रबंधन, शिक्षक भर्ती और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित नीतिगत सुधारों से इसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी हितधारकों की चिंताओं को समान रूप से संबोधित किया जाए ताकि शिक्षा का समावेशी और समग्र विकास हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, आर., एंड सिंह, बी. (2013). यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन विद द लेंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. शिक्षण अवेषिका, 3(2), 25-30.
2. शाहजेब, एस.एम., एंड खान, एम.ए. (2024). एक्सेस, क्वालिटी एंड आउटकम अंडर द सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) सब्जेक्ट टु प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. सऊदी जे इकोनॉमिक्स, 8(2), 55-66.
3. वार्ड, एम. (2011). एड टू एजुकेशन: द केस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया एंड द रोल ऑफ डेवलपमेंट पार्टनर्स. जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, 26(4), 543-556.
4. पटेल, डी. (2013). एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. एजुकेशन, 2(2), 39-48.
5. चक्रवर्ती, बी., कॉम्पटन, एम., एंड वीनर, एल. (2008). यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. द ग्लोबल असॉल्ट ऑन टीचिंग, टीचर्स एंड देयर यूनिवर्स, 143-148.
6. कौर, आर. (2013). यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया: द पॉलिसी पर्सपेक्टिव. एजुकेशन कॉन्फैब, 2(4), 204-213.
7. कुमार, आर., एंड सिंह, ए.के. (2022). अ ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट, झारखंड. ज्ञानशौर्यम, इंटरनेशनल साइंटिफिक रेफर्ड रिसर्च जर्नल, 05(01), 69-78.
8. कुमार, आर., एंड सिंह, ए.के. (2022). ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव इन द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन ट्राइबल चिल्ड्रन: अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. ज्ञानशौर्यम, इंटरनेशनल साइंटिफिक रेफर्ड रिसर्च जर्नल, 7(3), 106-112.
9. बंधोपाध्याय, एम. (2009). प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन स्कूल्स इन इंडिया: फ्रॉम नेशनल एंड स्टेट लेवल पर्सपेक्टिव. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. 7-17.
10. पाल, एस. (2010). पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल अटेनमेंट इन एन इमर्जिंग इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रिव्यू, 29(5), 783-794.